बढ़ती जनसंख्या : प्रशासन तंत्र की भूमिका

(कुछ सुझाव)

0 सुरेन्द्र कुमार कटारिया

संभवतः आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है - अबाध गति से बढ़ती जनसंख्या और आनुपातिक रूप से कम होते हमारे संसाधन । यूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष छोटा राष्ट्र नही है, कच्चे माल एवं तकनीक की दृष्टि से भी किसी से कम नहीं है। किन्तु आज की 86 करोड़ जनसंख्या जो संभवतः 20 वर्षों में चीन से भी अधिक हो जायेगी, के कारण राष्ट्र को अनेक समस्याओं एवं आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। कितनी विचित्र एवं हास्यास्पद बात है कि विश्व में सर्वप्रथम परिवार कल्याण कार्यक्रम (1952) प्रारम्भ करने वाला भारत देश स्वयं को परिवार नियंत्रित नहीं कर पाया। हरित क्रांति के पश्चात आई नई पीढ़ी को पता तक नहीं है कि देश के नागरिकों का पेट भरने के लिए हमें अमेरिका के सामने झोली फैलानी पड़ती थी। यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो समस्त खेतों में मकान, कल-कारखाने तथा सड़के होंगी एवं पुनः भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खटखटाने होंगे।

पिछले लम्बे समय से परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सरकारें एवं प्रशासन प्रक्रिया सुस्त सी रही है जो अचानक इन दिनों जागृत सी नजर आ रही हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस बार गंभीर प्रयास भी किये जा रहे हैं। यदि राष्ट्र के नेता तथा जनता सचमुच, राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु समन्वित प्रयासों की शीघ्र आवश्यकता है। इस हेतु कुछ सुझाव प्रस्तु हैं:

1. सर्वप्रथम केन्द्र एवं राज्य सरकारों में कार्यरत राजनीतिक पार्टियों सहित विपक्षी पार्टियों एवं अन्य राजनेताओं को इस बात के प्रति 'प्रतिबद्धता' सिद्ध करनी होगी कि वे सचमुच राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं। यदि यह प्रतिबद्धता कायम नहीं होती है तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। पंचायत चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर रोक लगाकर **'राजस्थान सरकार'** ने इसी प्रतिबद्धता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

2. आज नहीं तो कल जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अतः इसमें शीघ्र पहल क्यों नहीं की जा सकती है ? यदि हम तर्कसंगत कानून बनायेंगे तो बुद्धिजीवियों एवं जागरूक नागरिकों का सहयोग अवश्य मिलेगा । कुछ प्रावधान निम्न हो सकते हैं:-

Scanned with OKEN Scanner

1- राशन कार्ड में दो से अधिक बच्चों का नाम दर्ज नहीं होगा।

2- दो से अधिक बच्चे होने पर सरकार को अतिरिक्त कर (टेक्स) देना पड़ेगा।

3- सरकारी कर्मचारी के यदि दो से अधिक बच्चे हो तो वेतन वृद्धि रोकना, बोनस न देना, पदोन्नति रोकना तथा 'आवश्यक सेवा निवृति' भी प्रदान की जा सकती है।

4- दो बच्चे वाले किसानों को बिजली कनैक्शन, ऋण, खाद, बीज इत्यादि में सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि वे प्रोत्साहित हों ।

5- ग्राम पंचायतों के लिए नसबन्दी केस करवाना निर्धारित किया जाये ताकि गांव वाले दबाव में ही सही, नसबन्दी तो करवायें ।

6- यह निर्धारित कर दिया जोय कि जो कोई सन्तान पैदा करेगा वह उसे कम से कम प्राइमरी तक शिक्षा तो अवश्य ही दिलवायेगा अन्यथा जुर्माना देना होगा। शिक्षा के प्रसार के कारण जागृति पैदा होगी और वे शिक्षित बच्चे अपने भविष्य के प्रति 'संवेदनशील' बनेंगे।

3. नसबन्दी प्रोत्साहन राशि की मात्र इतनी होनी चाहिए, जितनी की कोई व्यक्ति एक सप्ताह में कमाता है। क्योंकि आज भी मजदूर एवं श्रमिक वर्ग यह सोचता है कि नसबन्दी के बाद सात दिन आराम करना है तो पैसा कहां से आयेगा। तथा सरकार को सुझाव है कि वह सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना बन्द कर दें क्योंकि उन्हें नसबन्दी के पश्चात अवकाश एवं वेतन तो मिलता ही है।

4. किसी भी स्त्री का गर्भवती हो जाना एक क्षणिक घटना है। इसके कुछ मानवीय पक्ष भी हैं । अतः अनेक बार दम्पति चाहते हैं कि गर्भपात करवा दिया जाये। किन्तु, स्वास्थ्य मंत्रालय को यह स्वीकार करके प्रयास करने चाहिए कि 'गर्भपात की सुविधा' आज भी जिला चिकित्सालयों तक में सुलभ नहीं है। चिकित्सक एवं नर्सें सहायता एवं मार्गदर्शन की बजाय झिड़की तथा गर्भपात की तकलीफें ज्यादा बताते हैं। वैसे भी गर्भपात की सुविधा कुछ ही जगहों पर उपलब्ध होने से अनचाही सन्तानें बहुत हो जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कृपया सर्वेक्षण कराये तथा सुधार करे। यह शीघ्र आवश्यक है।

5. ग्रीन कार्ड धारियों को देश में कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों सरकार झूठा प्रचार करती है ? समझ से बाहर है। कृपया इस हेतु नीति निर्धारित हो।

Scanned with OKEN Scanner

6. **वृद्धावस्था पेंशन** :- सबसे बड़ी समस्या एवं बढ़ती जनसंख्या के मूल में यही एक कारण है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो। जिसके दो लड़कियां हों या वह प्राइवेट संस्था में काम करता हो तो उसकी वृद्धावस्था पेंशन की यदि व्यवस्था हो जाये तो निस्संदेह जनसंख्या कम होगी। क्योंकि बुढ़ापे की चिन्ता में ही लड़का पैदा करने की चाह अधिक है। फिर चाहे वह धक्के मार के बाहर कर दे।

7. गांव में जो किसान मात्र कृषि पर आधारित हैं उनकी आजीविका का विकल्प 'कुटीर उद्योग' बढ़ाया जाये।

8. जिन लोगों से आस-पास के गांव-बस्ती सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं ऐसे संत, ओझा, बी.डी.ओ., राजनेता, अध्यापक, पंडित, सेठ, बड़ा जमींदार इत्यादि से छोटा परिवार रखने की सलाह एवं प्रचार करवाया जाये। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित कई तरह से किया जा सकता है।

9. विकास के माध्यम दो हैं :- शिक्षा एवं संचार । दुःख की बात है कि हम इन्ही दोनों क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। लड़कियों की शिक्षा, गांव-गांव में सड़क, बिजली, स्कूल, टी.वी तथा अस्पताल होने से जनसंख्या कम होगी। अतः इस हेतु व्यापक प्रयास हों।

10. जनसंख्या के खतरों के प्रति असरदार बातें प्रचारित की जायें। जैसे बसों, रेलों तथा सिनेमाघरों की टिकट खिडकियों पर लिखवाया जाये **'यह इतनी भीड़ क्यों है ? कभी सोचा आपने ?'** यकीन कीजिए यह एक अति असरकारक सन्देश है।

11. परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाये न कि कुछ रूपये या एक प्रमाण पत्र दें। यदि अभिप्रेरण का स्तर ऊंचा होगा तो कार्य स्तर भी उच्च ही होगा।

12. नई गर्भनिरोधक गोली 'सहेली' का प्रचार व्यापक स्तर पर शीघ्र किया जाये ताकि जनसाधारण लाभान्वित हो। हमारे यहां कुछ सैकन्ड़ों की देरी भी खतरनाक साबित होती है।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार कटारिया)
शोध अधिकारी,
भारत जनसंख्या परियोजना-6
शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
मुनीरका, नई दिल्ली-110067.

Scanned with OKEN Scanner